प्रेषक.

राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी,नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग-7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक २ अगस्त, 2012 विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 में राजकीय महाविद्यालय रामनगर, के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या डिग्री विकास/ 987/2012—13 दिनांक 26.04.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है चालू वित्तीय वर्ष 2012—13 में जनपद नैनीताल के अर्न्तगत रामनगर के पी०जी० ब्लाक के निर्माण हेतु अवशेष रु० 69.50 लाख की धनराशि के सापेक्ष रु० 50.00 लाख (रु० पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2— स्वीकृत धनराशि को निर्धारित कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई व्यय नहीं किया जायेगा एवं समय—समय पर निर्गत वित्तीय एवं मित्तव्ययता सम्वन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के

उपरान्त सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त की जाय।

3— स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा। निर्माण कार्य के लिये स्वीकृत की गई धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2013 तक सुनिश्चित किया जाय। तथा प्राचार्य द्वारा समुचित पर्यवेक्षण किया जायेगा एवं निर्माण इकाई द्वारा विलम्ब करने की दशा में शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी तथा आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

4— निदेशक उच्च शिक्षा कार्यदाई संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व कार्यदाई संस्था से एक सप्ताह में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के विरुद्ध एकेडिमिक रिक्वायरमेंट के अनुरुप समय सारणी अनुसार कार्य पूर्ण करने की लिखित सहमति प्राप्त कर लेगें। यदि लिखित समयावधि के अर्न्तगत कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो, एक माह का ग्रेस पीरियड देते हुये कार्यदाई संस्था से 5 प्रतिशत आर्थिक जुर्माना वसूला जायेगा। तीन माह से अधिक विलम्ब होने पर कार्यदाई संस्था को काली सूची में सम्मिलित करने हेतु कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। 5— उक्त निर्माण कार्य में आर.सी.सी. फ्रेम स्ट्क्चर, जो भू वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार प्राविधानित किया गया है, के सम्बन्ध में प्राचार्य द्वारा सुसंगत अभिलेखों में तकनीकी पुष्टि किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाय। उक्त रिपोर्ट से शासन को अवगत कराया जाय।

6— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012—13 के आय—व्ययक की अनुदान सं0 11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखा शीर्षक—4202—शिक्षा खेल कूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय—01—सामान्य शिक्षा—203—विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा—आयोजनागत—04—राजकीय महाविद्यालयों के भूमि/भवन क्य—24—बृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 54 (p)/xxvii(3) /2012 दिनांक 03 अगस्त, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(राकेश शर्मा) प्रमुख सचिव

सं0 62 % (1)/xxiv(7)/2012-48(2)/08 तद्दिनांक

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- 2- आयुक्त कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 3- जिलाधिकारी नैनीताल।
- 4- कोषाधिकारी हल्द्वानी-नैनीताल।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग रामनगर।
- 6- प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय रामनगर नैनीताल।
- 7-निदेशक एन०आई०सी० सचिवालय उत्तराखण्ड।
- 8- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
- 9- वित्त अनु0-3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।

10-गार्ड फाईल।

)आज्ञा से,

(वदीराम) अनु सचिव